International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 09, September 2020
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

नई ि"ाक्षा नीति–2020 : अवसर एवं चुनौतियां

डॉ.विष्णु कुमार शुक्ल
(असि.प्रो, अर्थ"ाास्त्र)
सी.जी.एन. (पी.जी.) कॉलेज, गोला गोकर्णनाथ–खीरी

ि"ाक्षा का अर्थ सीखने की प्रक्रिया से है। यह एक ऐसा साधन है जो दे"ा के बच्चों से लेकर युवाओं तक के भविष्य का निर्माण करता है। ऐसे मे यह आव"यक हो जाता है कि दे"ा को विकास की गति देने वाली ि"ाक्षा व्यवस्था भी प्रावैगिक हो। जीवन में ि"ाक्षा के महत्व को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण ि"ाक्षा उपलब्ध कराने के उदे"य से वर्तमान सरकार ने ि"ाक्षा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तनों को मंजूरी दी है। करीब तीन दशक के बाद दे"ा में नई ि"ाक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। इससे पूर्व वर्ष 1986 में राष्ट्रीय ि"ाक्षा नीति बनाई गई थी और वर्ष 1992 में इसमें सं"ाोधन किया गया था। उम्मीद की जा रही है कि यह ि"ाक्षा नीति ि"ाक्षा क्षेत्र में नवीन और सर्वांगीण परिवर्तनों की आधार ि"ाला रखेगी। राष्ट्रीय ि"ाक्षा नीति, 2020 को तैयार करने के लिये वि"व की सबसे बड़ी पराम"र्ा प्रक्रिया आयोजित की गयी थी। जिसमें दे"ा के विभिन्न वर्गो से रचनात्मक सुझाव भी माँगे गए थे। प्राप्त सुझावों और विभिन्न ि"ाक्षाविदों के अनुभवों तथा के. कस्तूरीरंगन समिति की सिफारि"ाों के आधार पर ि"ाक्षा तक सबकी आसान पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई ि"ाक्षा नीति सतत विकास के एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उदे"य 21वीं शताब्दी की आव"यकताओं के सापेक्ष स्कूल और कॉलेज की ि"ाक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वै"ि"वक महा"ाक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।

भारतीय ि"ाक्षा की विकास यात्रा

a. राश्ट्रीय ि"ाक्षा नीति, 1968

- स्वतंत्र भारत में ि"ाक्षा यह पहली नीति कोठारी आयोग (1964–1966) की सिफारि"ाों पर आधारित थी।
- ि"ाक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया।
- 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिये अनिवार्य ि"ाक्षा का लक्ष्य ओर ि"ाक्षकों को बेहतर प्रि"ाक्षण और योग्यता पर फोकस।
- ि"ाक्षा नीति ने प्राचीन संस्कृत भाषा के ि"ाक्षण को भी प्रोत्साहित किया, जिसे भारत की संस्कृति और विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता था।
- ि"ाक्षा पर केन्द्रीय बजट का 6 प्रति"ात व्यय करने का लक्ष्य रखा।
- माध्यमिक स्तर पर 'त्रिभाषा सूत्र' लागू करने का आह्वान किया गया।

b. राश्ट्रीय ि"ाक्षा नीति, 1986

- इस नीति का उदे"य असमानताओं को दूर करने वि"ोष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिये शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर वि"ोष जोर देना था।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 09, September 2020
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

- इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिये 'ऑपरे"ान ब्लैकबोर्ड' लागू किया।
- इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त वि"वविद्यालय के साथ 'ओपन यूनिवर्सिटी' प्रणाली का विस्तार किया।
- ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के द"ान पर आधारित 'ग्रामीण वि"वविद्यालय' मॉडल के निर्माण के लिये नीति का आह्वान किया गया।

c. राश्ट्रीय ि"ाक्षा नीति में सं"ाोधन, 1992

- राष्ट्रीय ि"ाक्षा नीति, 1986 में सं"ाोधन का उदे"य दे"ा में व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवे"ा के लिये अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवे"ा परीक्षा आयोजित करना था।
- इंजीनियरिंग और अर्किटेक्चर कार्यक्रमों में प्रवे"ा के लिये सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवे"ा परीक्षा (Joint Entrance Examination.JEE) और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवे"ा परीक्षा (All India Engineering Entrance.AIEE) तथा राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवे"ा परीक्षा (SLEEE) निर्धारित की।
- इससे प्रवे"ा परीक्षाओं की बहुलता के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों पर शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बोझ को कम करने की समस्याओं को हल किया।

ि"ाक्षा नीति में परिवर्तन की आव"यकता क्यों?

- बदलते वै"वक परिदृ"य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आव"यकताओं की पूर्ति करने के लिये मौजूदा ि"ाक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आव"यकता थी।
- ि"ाक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये नई ि"ाक्षा नीति की आव"यकता थी।
- भारतीय ि"ाक्षण व्यवस्था की वै"वक स्तर पर पहुँच सुनि"चत करने के लिये ि"ाक्षा नीति की आव"यकता थी।

d. राश्ट्रीय ि"ाक्षा नीति, 2020

- राष्ट्रीय ि"ाक्षा नीति–2020 में ि"ाक्षा की पहुँच,समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर वि"ोष ध्यान दिया गया है। नई ि"ाक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से ि"ाक्षा क्षेत्र पर दे"ा की जीडीपी के 6 प्रति"ात हिस्से के बराबर निवे"ा का लक्ष्य रखा गया है। नई ि"ाक्षा नीति के अंतर्गत ही 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development- MHRD) का नाम बदल कर ि"ाक्षा मंत्रालय (Education Ministry) करने को भी मंजूरी दी गई है।

नई ि"ाक्षा नीति के प्रमुख बिन्दु

i. प्रारंभिक ि"ाक्षा से सम्बन्धित प्रावधान

- 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये शैक्षिक प्राठ्यक्रम का दो समूहों मे विभाजन।
- नई ि"ाक्षा नीति में अब स्कूली ि"ाक्षा को 5+3+3+4 फार्मूले के अन्तर्गत पढ़ाया जाएगा।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 09, September 2020
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

○ 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये ऑगनवाड़ी/प्री–स्कूल (Pre-School) के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (Early Childhood Care and Education- ECCE) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

○ 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी।

○ प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी।

○ नई शिक्षा नीति मे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Foundation Literacy and Numeracy) की स्थापना की मांग की गई है।

○ राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी।

ii. भाशायी विविधता को संरक्षण

○ नई शिक्षा नीति -2020 में कक्षा–5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा–8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

○ स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परन्तु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

iii. पाठ्यक्रय और मूल्यांकन सम्बन्धी सुधार

○ इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।

○ कक्षा–6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप (Internship) की व्यवस्था भी दी जाएगी।

○ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of Education Research and Training- NCERT) द्वारा स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (National Curricular Framwork for School Education) तैयार की जाएगी।

○ छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान मे रखते हुए कक्षा–10 और कक्षा–12 की परीक्षाओं में बदलाव किये जाएंगे। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।

○ छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक–निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) एक नए राष्ट्रीय आंकलन केंद्र (Nationa Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी

○ छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने मे सहायता प्रदान करने के लिए 'कृत्रिम बुद्धिमता' (Artificial Intelligence-AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग।

iv. शिक्षण व्यवस्था से सम्बन्धित सुधार

○ शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय–समय पर लिये गए कार्य–प्रदर्शन आंकलन के आधार पर पदोन्नति।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 09, September 2020
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

○ राष्ट्रीय अध्यापक ि"ाक्षा परिषद वर्ष 2022 तक 'ि"ाक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (National Professional Standards for Teachers-NPST) का विकास किया जाएगा।

○ राष्ट्रीय अध्यापक ि"ाक्षा परिषद द्वारा NCERT के पराम"ार् के आधार पर अध्यापक ि"ाक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (National Curriculum Framwork for Teacher Education-NCFTE) का विकास किया जाएगा।

○ वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4–वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

v. उच्च ि"ाक्षा से संम्बन्धित प्रावधान

○ नई ि"ाक्षा नीति-2020 के तहत उच्च ि"ाक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपालन (Gross Enrolment Ratio) को 26.3 प्रति"ात (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50 प्रति"ात तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही दे"ा के उच्च ि"ाक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।

○ नई ि"ाक्षा नीति -2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिगी या प्राण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

○ 1 वर्ष के बाद प्रमाण–पत्र, 2 वर्षो के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षो के बाद स्नातक की डिगी तथा 4 वर्षो के बाद शोध के साथ स्नातक।

○ विभिन्न उच्च ि"ाक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (Academic Bank of Credit-ABC) दिया जाएगा, जिससे अलग– अलग संस्थानों में छात्रों के प्रद"र्ान के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।

○ नई ि"ाक्षा नीति के तहत एम.फिल (M.Phil) कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जायेगा।

vi. भारत उच्च ि"ाक्षा आयोग

○ चिकित्सक एवं कानूनी ि"ाक्षा को छोड़कर पूरे उच्च ि"ाक्षा क्षेत्र के लिये एकल निकाय के रूप में भारत उच्च ि"ाक्षा आयोग (Higher Education Commission of India -HECI) का गठन किया जाएगा।

○ HECI के कार्यो के प्रभावी और पारदर्ि"ातापूर्ण निष्पादन के लिये चार संस्थानों/निकायों का निर्धारण किया गया है।

○ विनियमन हेतु– राष्ट्रीय उच्चतर ि"ाक्षा नियामकीय परिषद (National Higher Education Regulatory Council- NHERC)

○ मानक निर्धारण– सामान्य ि"ाक्षा अनुदान परिषद (General Education Council-GES)

○ वित्त पोषण–उच्चतर ि"ाक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council-HEGC)

○ प्रत्यायन– राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (National Asseessment and Accreditation Council-NAAC)

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 09, September 2020
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

○ दे"ा में आई.आई.टी (IIT) और आई.आई.एम (IIM) के समकक्ष वै"िवक मानकों के बहुविषयक ि"क्षा एवं अनुसंधान वि"वविद्यालय (Multidiscipinary Education and Research Universities-MERU) की स्थापना की जाएगी।

नई ि"क्षा नीति की चुनौतियाँ

a. महंगी ि"क्षाः नई ि"क्षा नीति में विदे"ाी वि"वविद्यालयों के प्रवे"ा का मार्ग प्र"स्त किया गया है, विभिन्न ि"क्षाविदों का मानना है कि विदे"ाी वि"वविद्यालयों के प्रवे"ा से भारतीय ि"क्षण व्यवस्था महंगी होने की संभावना है। परिणामस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिये उच्च ि"क्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।

b. ि"क्षकों का पलायनः विदे"ाी वि"वविद्यालयों के प्रवे"ा से भारत के दक्ष ि"क्षक भी इन वि"वविद्यालयों में अध्यापन हेतु पलायन कर सकते है।

c. ि"क्षा का संस्कृतिकरणः दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि 'त्रि–भाषा' सूत्र से सरकार ि"क्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है।

d. संसद की अवहेलनाः विपक्ष का आरोप है कि भारतीय ि"क्षा की द"ाा व दि"ाा तय करने वाली इस नीति को अनुमति देने में संसद की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया। पूर्व में राष्ट्रीय ि"क्षा नीति– 1986 भी संसद के द्वारा लागू की गई थी।

e. मानव संसाधन का अभावः वर्तमान में प्रारंभिक ि"क्षा के क्षेत्र में कु"ाल ि"क्षकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय ि"क्षा नीति, 2020 के तहत प्रारंभिक ि"क्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएं है।

भारत में लगभग एक तिहाई बच्चे प्राथमिक ि"क्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ देते है। यह उल्लेखनीय है कि अधिकां"ा बच्चों, जो स्कूल जाने में असमर्थ हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यकों और दिव्यांग समूहों से सम्बन्धित है एक महत्वपूर्ण चुनौती बुनियादी ढांचे की कमी से सम्बन्धित है यह सामान्य रूप में देखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप ि"क्षा प्रणाली प्रभावित होती है। वि"व बैंक की वि"व विकास रिपोर्ट 2018 दी लर्निंग टू रियलाइज एजुके"ान प्रॉमिस के अनुसार, भारत की ि"क्षा प्रणाली बदतर स्थिति में है। ि"क्षा क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के विफल होने का खतरा है। इसका कारण ि"क्षा नीति में बदलाव करते समय रोडमैप का पालन नही करना और नीतियों को बनाते समय सभी हितधारकों को ध्यान में नहीं रखना है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों मे ि"क्षा के बुनियादी ढांचे में निवे"ा किया हो ऐसा हो सकता है लेकिन यह अपेक्षाकृत सफल नहीं रहा है। नई ि"क्षा नीति प्रणाली के सामने एक चुनौती ि"क्षकों की कमी को दूर करना भी है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षा (CAG) की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, एकल ि"क्षक के भरोसे बड़ी संख्या में स्कूल चल रहे हैं, जो ि"क्षा की गुणवत्ता को घटाता है यह उल्लेखनीय है कि बहुत कम भारतीय ि"क्षण संस्थानों को शीर्ष 200 वि"व रैंकिग में जगह मिलती है। ि"क्षा नीति के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती वि"वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसरों की जवाबदेही और प्रद"ान सुनि"चित करने से सम्बन्धित सूत्र को लागू करना भी है। आज दुनिया के कई वि"वविद्यालयों में अपने साथियों और छात्रों के प्रद"ान के आधार पर ि"क्षकों के प्रद"ान का मूल्यांकन किया जाता है। श्वांस और बकेट लिस्ट मसौदे मे त्रिभाषी नीति भी नई ि"क्षा नीति-2020 के सामने एक चुनौती पे"ा कर रही है, जिसमें गैर हिन्दी भाषा क्षेत्रों में मातृ–भाषा और अंग्रेजी भाषा के अलावा हिंदी को तीसरी भाषा बनाने की सिफारि"ा की गई है। तीन भाषा सूत्र नया

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 09, September 2020
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

नहीं है और पिछली ि"ाक्षा नीतियों में 1968 और 1986 में इसकी पहले से ही सिफारि"ा की गई थी। निष्कर्ष रूप में, यह कहा जा सकता है कि नीति-2020 सरकार द्वारा ि"ाक्षा प्रणाली में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी है। उल्लेखनीय है कि इन चुनौतियों से निपटने का प्रयास पूर्व में भी किया जा चुका है, लेकिन उपलब्धियाँ सराहनीय नहीं रही है। इस संदर्भ में कुछ सुझावों को यहां लागू करने की आव"यकता है। इस नीति के तहत, ि"ाक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार, नागरिकों सामाजिक संस्थाओं, वि"ोषज्ञो, अभिभावकों, समुदाय के सदस्यों को अपने स्तर पर काम करना चाहिए। शैक्षिक संस्थान, कार्यान्वयन एजेंसियों, छात्रों और औद्योगिक क्षेत्रों के नेताओं के बीच एक सहजीवी सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए। इसलिए , नवाचारों का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सकता है। जिसमें रोजगार के बड़े अवसर पैदा हो सकता है। इसके लिए यह आव"यक है कि ि"ाक्षक संस्थानों से जुड़े हों। इसके अलावा कार्पोरेट प्रतिष्ठानों के वि"ोष महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए और दे"ा के डाक्टरों और पोस्ट–डॉक्टोरल प्रोग्रामों के अनुसंधान के लिए वित्त प्रदान करना चाहिए।

एक मजबूत रेटिंग प्रणाली वि"वविद्यालय के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगी और उनके प्रद"र्न में सुधार करेगी। भारतीय वि"वविद्यालय अभी भी दुनिया के शीर्ष 200 रैंक वाले वि"वविद्यालयों में शामिल नहीं है ि"ाक्षा इस सम्बन्ध में वि"वविद्यालययों और ि"ाक्षाविदों को सम्बन्धित मानकों में आत्मनिरीक्षण और सुधार करना चाहिए। स्कूली ि"ाक्षा में सुधार के अलावा ि"ाक्षण और प्रि"ाक्षण विधियों में भी सुधार किया जाना चाहिए एक ओर संस्थान की स्वायत्तता की वकालत की जाती है, जबकि दूसरी ओर मौजूदा व्यवस्था में यदि आप वि"वविद्यालय के भीतर एक संगोष्ठी तक आयोजित करना चाहते है। तो आपको कुलपति से अनुमति लेनी होगी। एक और उदाहरण में, एक तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत की जाती है और दूसरी तरफ दे"ा की सरकार के मंत्री ऐसे भाषण देते है जो अंधवि"वास को बढ़ावा देते है। इसी तरह इस नई ि"ाक्षा नीति-2020 का वक्तव्य बहुत अच्छा है ब"र्ते यह वास्तव में लागू हो। यदि सरकार इसे अपनी भावना और मन में लाये और इसके आधार पर मूल ढांचे को बदलने के इरादे से पूरी शैक्षिक संरचना पर काम करे तभी कुछ संभव है। सिर्फ अच्छे शब्दों से काम नही चलेगा। इसके क्रियान्वयन पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए। हमे आने वाले द"ाकों में यह भी देखना होगा कि सरकारें नई ि"ाक्षा नीति-2020 के अनुसार कानूनों को बदलने के बाद आव"यक अतिरिक्त बजट प्रदान करने और उसे खर्च करने में सक्षम है या नहीं।

निश्कर्श

नई ि"ाक्षा नीति के तहत सरकार का उदे"य ऐसी ि"ाक्षण प्रणाली विकसित करना है, जहां बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को ि"ाक्षा का समान अवसर मिले और उनका विकास हो। दे"ा के दूर–दराज के क्षेत्रों में वि"ोष ि"ाक्षा क्षेत्र भी स्थापित किए जाये। वर्ष 2030 तक सभी बच्चों तक ि"ाक्षा की पहुच सुनि"चित करना भी ि"ाक्षा नीति का हिस्सा है। उच्च ि"ाक्षा तंत्र मे व्यापक सुधार करते हुए दे"ाभर में वि"वस्तरीय और विविध विषयों पर आधारित उच्च शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण, वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात को न्यूनतम 50 प्रति"ात तक बढ़ाने का लक्ष्य रख गया है सभी उच्च ि"ाक्षण बहुविषयक संस्थानों मे होंगे। संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से सभी विषयों और क्षेत्रों के अध्ययन को सुविधाजनक बनाया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण ि"ाक्षा उपलब्ध कराने वाले बहुविषयक संस्थान, जो भारत में उच्च ि"ाक्षा में अनिवार्य अंग होगा। उच्च गुणवत्ता पर आधारित

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 09, September 2020
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

तीन प्रकार के सस्थान होंगे। जिसमें पर्याप्त सार्वजनिक निवे"ा किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक ि"ाक्षा का विस्तार और विकास होगा। भौगोलिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को वरीयता दी जाएगी। अगले पांच वर्षो के भीतर प्रत्येक जिले में कम से कम एक टाइप–1 संस्थान होगा। सभी उच्च ि"ाक्षा संस्थान या तो वि"वविद्यालय होंगे या डिग्री प्रदान करने वाले स्वायत्त महाविद्यालय। किसी प्रकार के वि"वविद्यालय या महाविद्यालय नहीं होंगे। छात्रों के बहुमुखी विकास के लिए कल्पना"ाील और व्यापक तौर पर उदार ि"ाक्षण व्यवस्था बनाने की पहल होगी। चुने गए विषय और में वि"ोषज्ञता पर जोर दिया जाएगा।

21वीं सदी के भारत की आव"यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय ि"ाक्षा प्रणाली में परिवर्तन हेतु जिस नई ि"ाक्षा नीति–2020 को अपनाया जा रहा है यदि इसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह प्रणाली भारत को वि"व के अग्रणी–दे"ाों के समकक्ष ले जायेगी। नई ि"ाक्षा नीति के अन्तर्गत 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को ि"ाक्षा का अधिकार कानून– 2009 के तहत रखा गया है। 34 वर्षो के प"चात् प्रारम्भ की जा रही इस ि"ाक्षा नीति का उद्दे"य सभी छात्रों को उच्च ि"ाक्षा प्रदान करना है जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व–प्राथमिक ि"ाक्षा (3–6 वर्ष) को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक ि"ाक्षा में आर्टिफि"ायल, इंटेलीजेंस, थ्री डी म"ाीन, डेटा वि"लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावे"ान से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कु"ाल कामगार तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ/पत्र–पत्रिकाएँ

1. 'राष्ट्रीय ि"ाक्षा नीति'–2020
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
2. नई ि"ाक्षा नीति–2020: उच्च ि"ाक्षा पर धारणा
एम.एल. गोयल
3. Chaube S.P. (1988) History And Problems & Indian Education
(Second Edi.) Vinod Pustak Mandir, Agra U.P.
4. Rawat P.L.: History of Indian Education
(Ram Prasad & Sons, Agra U.P.)
5. भारत मे ि"ाक्षा नीति की द"ाा एवं दि"ाा
(Ram Prasad & Sons, Agra U.P.)
6. भारतीय आर्थिक समस्याएँ: टी.आर. जैन तथा मुके"ा जैन
(Global Publication PVT Ltd,New Delhi)
7. Indian Economy: V.K.Puri & S.K. Mishra
(Himalaya Publishing House Pvt. Ltd.)
8. दैनिक समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ (दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, अमर उजाला एवं सम–सामयिक पत्रिकाएँ।